

दो पायलट कॉकपिट में थे, दो यात्रियों के बीच बैठे थे

फ्लाईदुबई की उड़ान में चार पायलट क्यों थे, हमले के बाद दो ने संभाला विमान

विमान करीब 17 हजार फीट नीचे आया, अतिरिक्त पायलटों ने संभाली कमान

तेल अवीव, एजेंसी: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में कुल चार पायलट सवार थे। उड़ान के दौरान को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित माछर पर हमला कर दिया। हमले में कैप्टन घायल हो गए। इसके बाद उन्होंने किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोला, जिसके बाद यात्रियों और चालक दल की मदद से दो अन्य पायलट कॉकपिट में पहुंचे और विमान की कमान संभाली। विमान को सुरक्षित रूप से सऊदी अरब के तबुक में उतारा गया। उड़ान के दौरान विमान तेजी से नीचे आया था। एविएशन सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, विमान को संभालने में कुछ सेकेंड की और देरी होती तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी।

कैप्टन के कॉकपिट का दरवाजा खोलने और आपात संकेत देने को महत्वपूर्ण बताया गया है। अब सवाल यह है कि करीब साढ़े तीन घंटे की इस उड़ान में दो अतिरिक्त पायलट क्यों मौजूद थे। विशेषज्ञों के



मुताबिक, छोटी उड़ानों में अतिरिक्त पायलटों को केवल आपात स्थिति के लिए बैकअप के तौर पर रखना सामान्य व्यवस्था नहीं है। पायलटों की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च के कारण एयरलाइंस

जरूरत के मुताबिक ही चालक दल रखती हैं। रियार्ड एयरलाइन कैप्टन और विमानन सुरक्षा सलाहकार जॉन कॉक्स के मुताबिक, दोनों अतिरिक्त पायलटों को संभवतः उनकी अगली उड़ान के लिए जरूरी

स्थान तक पहुंचाया जा रहा था। विमानन क्षेत्र में इसे 'डेडेडिंडे' कहा जाता है। फ्लाईदुबई के अनुसार, ये पायलट कंपनी के ड्यूटी पर तैनात चालक दल का हिस्सा थे। एक दूसरी वजह वापसी की

निर्धारित ड्यूटी सीमा पूरी हो सकती है। इसे 'टाइमिंग आउट' कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वापसी की उड़ान के लिए दूसरे पायलटों को पहले ही भेजा जा सकता है।

रियार्ड कैप्टन रिचर्ड लेवी ने कहा कि गंभीर स्थिति के बावजूद विमान का उड़ते रहना और सुरक्षित उतरना महत्वपूर्ण था। विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ सैली लीव्सली के मुताबिक, क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के कारण उड़ानों में देरी की स्थिति में अतिरिक्त पायलट चालक दल और उड़ान कार्यक्रम को संभालने में मदद कर सकते हैं।

हमले में इस्तेमाल हथियार को लेकर शुरुआती जानकारी में चाकू का उल्लेख था। बाद में संयुक्त अरब अमीरात के सरकारी वकील ने बताया कि को-पायलट ने कॉकपिट में रखी आपातकालीन कुल्हाड़ी से कैप्टन पर हमला किया था। बोइंग 737 जैसे विमानों में ऐसी कुल्हाड़ी आपातकालीन उपकरण के रूप में रखी जाती है।

एयर चीफ मार्शल बोले- फाइटर स्वतःइन घटकर 29 हुई, राफेल और तेजस से स्थिति सुधारने की उम्मीद

तेजस की डिलीवरी में हो रही देरी से वायुसेना को नुकसान, हर साल 36-40 लड़ाकू विमान चाहिए

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को कहा कि तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी से वायुसेना को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में वायु शक्ति का महत्व बढ़ रहा है, जबकि वायुसेना के लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 29 रह गई है। आधिकारिक स्वीकृत संख्या 42 स्क्वाड्रन है। वायुसेना को अगले कुछ वर्षों तक हर साल कम से कम 36 से 40 लड़ाकू विमानों की जरूरत है।

एयर चीफ ने कहा कि तेजस मार्क-1ए और फ्रांस से मिलने वाले राफेल विमानों की आपूर्ति से स्थिति में सुधार की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वायुसेना को तेजस मार्क-2 और एडवॉंस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमसीए)



का भी इंतजार है। भारत ने फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 83 तेजस मार्क-1ए विमानों के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का समझौता किया था। इन विमानों की पहली खेप मार्च 2024 में मिलने की योजना थी, लेकिन डिलीवरी में देरी हुई है। पिछले वर्ष सितंबर में 97 और तेजस मार्क-1ए विमानों

की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपये का समझौता किया गया था। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि भारत 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (एमआरएफए) की खरीद के लिए लंबित सौदे को इसी वित्त वर्ष में अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है। यह सौदा फ्रांस से राफेल विमानों की खरीद से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि योजना

के अनुसार काम हुआ तो सौदे पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। एएमसीए कार्यक्रम में देरी की स्थिति में दूसरे लड़ाकू विमान प्लेटफॉर्म पर विचार करने की संभावना भी जताई गई है। रूस ने भारत को एसयू-57 विमानों की पेशकश की है, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। थिएटर कमांड को लेकर एयर चीफ ने कहा कि वायुसेना इसके खिलाफ नहीं है और इस दिशा में काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव के बाद थिएटराइजेशन पर चर्चा की दिशा में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सेना सरकार के सामने उपलब्ध विकल्प रखेगी और अंतिम निर्णय सरकार करेगी। प्रस्तावित व्यवस्था में थलसेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर अभियानों में बेहतर तालमेल बनाने की योजना है।

इमरान की पार्टी और पाकिस्तान सरकार में बातचीत, इस्लामाबाद मार्च टालने पर चर्चा

► पीटीआई ने इमरान से मुलाकात और अस्पताल में इलाज की मांग रखी, 4 अक्टूबर के मार्च को लेकर दोनों पक्षों में गतिरोध

इस्लामाबाद, एजेंसी: पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और सरकार के बीच शनिवार को दूसरे दौर की बातचीत हुई। बैठक में 4 अक्टूबर को प्रस्तावित इस्लामाबाद मार्च को टालने और राजनीतिक तनाव कम करने पर चर्चा हुई। बातचीत नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक के कक्ष में हुई, जिसमें सरकार, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीटीआई के प्रतिनिधि शामिल हुए। पीटीआई ने मांग रखी कि उसके संस्थापक इमरान खान से तुरंत मुलाकात की अनुमति दी जाए और उन्हें अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पार्टी ने इमरान की बहनों तथा



प्रदर्शन से पहले गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों को रिहा करने की मांग भी रखी। इसके अलावा इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की चिकित्सकीय जांच और उनके खिलाफ चल रहे मामलों की स्वतंत्र सुनवाई की मांग की गई। सरकार की ओर से पीटीआई से 4 अक्टूबर को प्रस्तावित मार्च रद्द करने की मांग की गई है। शुक्रवार को हुई पहली बैठक में दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष रखे

थे, लेकिन किसी समझौते पर सहमति नहीं बनी। दोनों पक्षों ने शनिवार को फिर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई थी।

पीटीआई ने पहले 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकालने की घोषणा की थी, जिसे बाद में एक सप्ताह के लिए टालकर 4 अक्टूबर कर दिया गया। पार्टी के अनुसार मार्च खेबर पख़ूनखा से शुरू होकर इस्लामाबाद की ओर बढ़ेगा। राजधानी में प्रस्तावित

प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और कई मार्गों पर कंटेनर लगाए गए हैं। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उनका कहना है कि देश के मुद्दों और राजनीतिक मतभेदों के समाधान के लिए संसद बातचीत का मंच है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ चल रहे मामलों पर फैसला अदालतों को करना है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें तोशाखाना मामले में सजा के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ सिफर, अल-कादिर ट्रस्ट और इदत निकाह सहित अन्य मामले चले। पीटीआई इन मामलों को राजनीतिक कार्रवाई बताती रही है, जबकि सरकार और जांच एजेंसियां इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताती हैं।

व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम पर हथियारों की तस्करी और बिक्री को लेकर बातचीत का आरोप

नईदुनिया ब्यूरो, बीदर: कर्नाटक के बीदर जिले में पुलिस ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप में 24 वर्षीय विशाल कुमार मेट्टे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, विशाल पाकिस्तान में मौजूद शहजाद भट्टी, राणा हनैन और नोमी खान के संपर्क में था। खुफिया जानकारी के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। वह बीदर के भालकी तालुका स्थित येनकूर गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, विशाल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए शहजाद भट्टी के संपर्क में था।

पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े कर्नाटक के युवक को गिरफ्तार किया

आरोप है कि उसके और नोमी खान के बीच अवैध हथियारों की तस्करी और बिक्री को लेकर बातचीत हुई थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के जरिए हथियारों या पैसों का कोई लेनदेन हुआ था या नहीं। पुलिस ने बताया कि विशाल का संपर्क उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी आशु शर्मा और मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी राज भाई उर्फ

लकी सिंह से भी था। पुलिस के अनुसार, विशाल दिसंबर 2025 से देश-विरोधी गतिविधियों से जुड़ा था और तभी से उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी। खटक चिंचोली पुलिस थाने में विशाल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, पृष्ठताल में विशाल ने आतंकी संगठनों और अवैध हथियार नेटवर्क से संबंध होने से इनकार किया था। उसने शुरुआत में मोबाइल फोन देने से भी मना किया, लेकिन बाद में फोन पुलिस को सौंप दिया। मोबाइल की प्रारंभिक जांच और व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम की पड़ताल में उसके संपर्कों का पता चला। प्राथमिकी के अनुसार, राणा हनैन ने विशाल को 'राहे हक' और 'राणा भाई 333' नाम के व्हाट्सएप चैनलों के लिंक भेजे थे।

सीमा पर दो लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को किया तलब

इस्लामाबाद, एजेंसी: पंजाब के तरनतारन जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान ने शनिवार को भारतीय राजनयिक को तलब कर विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि दोनों पाकिस्तानी नागरिक थे और सीमा सुरक्षा बल की गोलीबारी में मारे गए। वहीं, भारतीय अधिकारियों के अनुसार दोनों भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ रहे थे।

थे। शुक्रवार को तीन संदिग्ध लोग पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे। बीएसएफ जवानों ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी। इनमें से एक व्यक्ति वापस पाकिस्तान की ओर चला गया, जबकि दो आगे बढ़ते रहे। इसके बाद बीएसएफ ने गोलीबारी की, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दोनों मृतकों को निहत्था नागरिक बताते हुए कहा कि वे अज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे।

एक लाख से अधिक यमनी सैनिकों की तैनाती संभव

रियाद, एजेंसी: सऊदी अरब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। क्षेत्रीय और पश्चिमी अधिकारियों के अनुसार, अभियान के आकार के आधार पर एक लाख से अधिक यमनी सैनिकों को जुटाया जा सकता है। इसका प्रमुख उद्देश्य लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित रणनीतिक बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास हतियारों के हालिया कब्जे को पीछे हटाना और समुद्री मार्ग को सुरक्षित करना है। अभियान आने वाले सप्ताहों में शुरू होने की संभावना बताई गई है। बाब-अल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और एशिया तथा यूरोप के बीच महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग का हिस्सा है। हूतियों ने पिछले महीने यमन के तटीय इलाकों में तेजी से बढ़त बनाते हुए इस क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत किया था। सऊदी अरब को आशंका है कि वहां हूतियों का नियंत्रण बना रहने से समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। सऊदी अरब सैन्य कार्रवाई के दो विकल्पों पर विचार कर रहा है। पहले विकल्प में बाब-अल-मंदेब के आसपास सीमित अभियान चलाकर तटीय क्षेत्र को वापस लेने

की कोशिश होगी। दूसरे विकल्प में यमन के अल-बायदा, मारिब, ताइज और अल-जौफ प्रांतों में एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई की जा सकती है। जमीनी अभियान यमनी बलों के नेतृत्व में होगा और उन्हें सऊदी अरब की हवाई सहायता मिल सकती है। अमेरिका सऊदी अभियानों के लिए खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है, जबकि उसके सिधे युद्ध में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। तुर्किये और पाकिस्तान की ओर से भी सैन्य सहायता उपलब्ध कराए जाने की जानकारी है। फ्रांस ने सऊदी अरब में रक्षात्मक प्रणालियां तैनात करने की घोषणा की है। हालांकि, सहयोगी देशों के सिधे युद्ध में शामिल होने की संभावना नहीं बताई गई है। सऊदी अरब के सामने यमन में सक्रिय विभिन्न हूती विरोधी गुटों के बीच समन्वय की कमी भी चुनौती है। इन गुटों के राजनीतिक और सैन्य हित अलग-अलग हैं। इसके अलावा, सऊदी अरब को अपने तेल ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की चिंता है। हूती पहले भी झोन और प्रक्षेपास्त्रों से सऊदी क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिश कर चुके हैं। अभियान की सटीक समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।

संकट

कमी हजारों प्रवासी पक्षियों का ठिकाना थी झील, कम बारिश, बढ़ती गर्मी और खेती के लिए पानी निकालने से बढ़ा संकट

कोरोनिया झील सूखने की कगार पर, 92% से घटा जल क्षेत्र

थेसालोनिकी, एजेंसी: ग्रीस की कोरोनिया झील पर जलवायु परिवर्तन, कम बारिश और बढ़ती गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तरी ग्रीस में स्थित यह झील कभी देश की पांचवीं सबसे बड़ी झील थी और यहां हजारों प्रवासी तथा जलीय पक्षी आते थे। आसपास के किसान और मछुआरे भी लंबे समय से झील पर निर्भर रहे हैं। अब झील का बड़ा हिस्सा सूख चुका है और कई जगह केवल कीचड़ तथा फटी हुई जमीन दिखाई दे रही है। नेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ एथेंस के आंकड़ों के अनुसार, 2016 में कोरोनिया झील की जल सतह 34.4 वर्ग किलोमीटर थी। अब यह घटकर केवल 2.7 वर्ग



किलोमीटर रह गई है। यानी करीब एक दशक में झील की जल सतह 92

प्रतिशत से अधिक कम हो गई है। कुछ हिस्सों में ही गंदला पानी छोटे-छोटे

तालाबों के रूप में बचा है।

खेती के लिए भी निकाला जा रहा पानी झील में पानी घटने के पीछे मानवीय इस्तेमाल भी एक कारण है। आसपास के किसान फसलों और मवेशियों के लिए झील के पानी का इस्तेमाल करते रहे हैं। बारिश कम होने पर सिंचाई की जरूरत बढ़ी, जिससे झील से पानी निकालने का दबाव भी बढ़ गया। झील की सुरक्षा को लेकर पहले भी कार्रवाई हुई है। 2013 में यूरोपीय संघ की अदालत ने ग्रीस को झील की सुरक्षा में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद पानी के इस्तेमाल और सिंचाई पर निगरानी बढ़ाई गई। कोरोनिया झील में पानी घटने का असर पक्षियों पर भी पड़ रहा है। यहां आने वाले फ्लेमिंगो समेत हजारों प्रवासी पक्षियों के रहने और भोजन की जगह लगातार कम हो रही है। कम बारिश से बढ़ा संकट 2015-16 के बारिश वाले मौसम के बाद झील में पानी की कमी तेजी से बढ़ी। इसके बाद कई वर्षों तक क्षेत्र में बारिश सामान्य से कम रही। पिछले कम से कम पांच वर्षों में यहां औसतन करीब 400 मिलीमीटर वार्षिक बारिश हुई, जो पिछले कई दशकों की तुलना में लगभग 150 मिलीमीटर कम है। बढ़ती गर्मी भी झील के पानी को तेजी से सुखा रही है। अनुमान के अनुसार, अधिक वाष्पीकरण के कारण हर साल करीब 100 से 150 मिलीमीटर पानी कम हो रहा है।

ममता की 2021 की पैर की चोट पर जांच



► शुभेंदु अधिकारी का दावा- रिपोर्ट में फ्रैक्चर या हड्डी खिसकने के प्रमाण नहीं, 9 अक्टूबर के बाद दंगे विस्तृत जानकारी

नईदुनिया ब्यूरो, कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी पैर की चोट को लेकर जांच की बात कही। अधिकारी ने दावा किया कि उस समय की मेडिकल रिपोर्ट में पैर में फ्रैक्चर या हड्डी खिसकने का कोई प्रमाण नहीं था। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद 9 अक्टूबर के बाद इस मामले में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

ममता बनर्जी ने 10 मार्च 2021 को नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार के दौरान पैर में चोट लगने की बात कही थी। उनके अनुसार, भीड़ के दबाव और धक्के के कारण कार का दरवाजा उनके बाएं पैर पर लगा था। इसके बाद उन्होंने पैर में प्लास्टर लगाकर

चुनाव प्रचार किया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार इस मामले की जांच कराएगी। उन्होंने दावा किया कि उपलब्ध चिकित्सा दस्तावेज में फ्रैक्चर का उल्लेख नहीं है। अधिकारी के मुताबिक, उपचुनाव के लिए लागू आचार संहिता के कारण फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस बीच, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद भी जारी है। निर्वाचन आयोग ने दोनों गुटों को अंतरिम तौर पर अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' चिह्न दिया गया है, जबकि दूसरे गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चिह्न मिला है। यह व्यवस्था आगामी उपचुनावों के लिए लागू है। नंदीग्राम 2021 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख सीट रही थी। ममता बनर्जी ने यहां से चुनाव लड़ा था, जबकि शुभेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ चुनाव जीत दर्ज की थी।